भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3497** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/ 30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है

बकिंघम नहर का विकास

† 3497. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के पूर्वी तट पर स्थित बकिंघम नहर का व्यापार और परिवहन में ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के हिस्से के रूप में विकसित करने की तत्काल आवश्यकता से अवगत है;

(ख) क्या बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इसके लिए योजना, समय-सीमा और बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) बकिंघम नहर के पुनरोद्धार से तटीय शहरों और बंदरगाहों के बीच कम खर्चीला और पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा तथा इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे है; और

(घ) क्या सरकार ने बकिंघम नहर के विकास के सामाजिक- आर्थिक लाभों का, विशेषकर पर्यटन और स्थानीय समुदायों, विशेषकर मछली पकड़ने और परिवहन के लिए आजीविका के अवसरों के संबंध में मूल्यांकन किया है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): बकिंघम नहर, जिसमें 316 कि.मी. लंबी उत्तर बकिंघम नहर (पेडागंजम से सेंट्रल स्टेशन चैन्ने) और 110 कि.मी. लंबी दक्षिण बकिंघम नहर (सेंट्रल स्टेशन चैन्ने से मरकानाम) शामिल है, राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (रा.ज.-4) की संघटक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा वर्ष 2008 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी और डीपीआर के उन्नयन का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएआई ने बकिंघम नहर में संभावित पर्यटन/ कार्गो आवाजाही की पहचान की है और तमिलनाडु सरकार से सहयोग के ढांचे के तहत कार्गो/नदी क्रूज पर्यटन परियोजनाएं शुरू

करने का अनुरोध किया है, क्योंकि बकिंघम नहर के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-2026 तक रा.ज.- 4 के लिए कुल 19.17 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ): बकिंघम नहर के पुनरोद्धार से मत्स्य / स्थानीय समुदायों/ उद्योगों के लिए संभार-तंत्र सस्ता होगा तथा सड़क से भीड-भाड़ में कमी आएगी। आईडब्ल्यूएआई द्वारा वर्ष 2008 में तैयार की गई डीपीआर में इस नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के सामाजिक/ आर्थिक लाभ शामिल हैं।

*****